



संघमित्र राज्य

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्रधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 85]
No. 85]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 2, 1990/फाल्गुन 11, 1911
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 2, 1990/PHALGUNA 11, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

विश्व संवत्सव
(राजस्व विभाग)
(विदेश का प्रमाण)

अधिसूचनाएं
नई दिल्ली, 2 मार्च, 1990
आय-कर

सा.का.नि. 107(अ).—आय और पूंजी पर करों की बाबत
दोहरे कराधान का परित्यक्त करने के लिए भारत गणराज्य और जर्मन
जनवादी गणराज्य की सरकार के बीच इससे उद्भव करार, दोनों संविदा-
कारी राज्यों द्वारा उनकी विधियों के अधीन करार के अनुमोदन के बाव
में उक्त करार के अनुच्छेद 31 के अनुसार एक दूसरे को अधिसूचित किए
जाने पर 24 नवम्बर, 1989 को प्रवृत्त हो गया है।

अनः प्रव. केन्द्रीय सरकार, धन कर अधिनियम, 1957 (1957
का 37) की धारा 44क और आय-कर अधिनियम, 1961 (1961
का 43) की धारा 90 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह
निर्देश देती है कि उक्त करार के सभी उद्देश्यों को भारत संघ में प्रभावी
किया जाएगा।

आय और पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार
के लिए भारत गणराज्य की सरकार और जर्मन जनवादी गणराज्य की
सरकार के बीच करार

भारत गणराज्य की सरकार
तथा
जर्मन जनवादी गणराज्य
के बीच

आय और पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार
के लिए करार

भारत गणराज्य की सरकार तथा जर्मन जनवादी गणराज्य की सरकार
आय और पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार के लिए
एक करार के माध्यम से दोनों राज्यों के बीच आर्थिक सहयोग के संबंधों
को उन्नत से नीचे निम्न अनुसार सहमत हुई है।—

अनुच्छेद-1
वैयक्तिक व्याप्ति

यह करार उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो किसी एक अथवा दोनों
संविदाकारी राज्यों के निवासी हैं।

अनुच्छेद-2

करार के अन्तर्गत आने वाले कर

1. जिन कर्षों पर यह करार लागू होगा वे हैं :—

(क) भारत गणराज्य के मामले में :—

- (i) आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) के अध्याधीन लगाया गया आयकर तथा आयकर पर लगाया गया कोई अधिभास्क, और
 - (ii) धनकर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के अध्याधीन लगाया गया धनकर
- (जिसे इसके बाद "भारतीय कर" कहा गया है)।

(ख) जर्मन जनवादी गणराज्य के मामले में :—

- (i) इन्कमेटैक्सट (आयकर)
 - (ii) कोर्पोरेटैक्सट (निगमित आयकर)
 - (iii) डीरेक्शन्सल डर स्टैटिक्वेन बेट्रिबे (सरकारी उद्यम द्वारा अन्तर्गत किया गया राजस्व)
 - (iv) लोह्वेस्टेयर (संजुरी पर कर)
 - (v) स्टैयर ऑफ़ डिर्जेस्वरहृगन (रायल्टियों पर कर)
 - (vi) इम्प्रेस्सगोर (आपावर कर) और
 - (vii) वारभोर्मेस्टयोर (सम्पत्ति कर)
- (जिसे इसके बाद "जर्मन जनवादी गणराज्य" कहा जाएगा)।

2. यह करार किन्हीं समस्त पक्षों पर्याप्त रूप से एक समान करें पर भी लागू होगा, जो दोनों संविदाकारी राज्यों में वे किन्हीं भी संविदाकारी राज्य द्वारा पैरा 1 में उल्लिखित कर्षों के अतिरिक्त अथवा उनके स्थान पर वर्तमान करार पर हस्ताक्षर करने को लागू के बाद लगाए जाएंगे।

संविदाकारी राज्यों के सशम प्राधिकारी अपने-अपने कराधान कानूनों में किए गए किन्हीं भी महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बारे में एक-दूसरे को अधिसूचित करेंगे।

अनुच्छेद-3

सामान्य परिभाषाएं

1. इस करार में जब तक विषयगत पाठ में अन्यथा अशेषित नहीं हो :—

- (क) "एक संविदाकारी राज्य" और "दूसरे संविदाकारी राज्य" शब्दों से विषयगत पाठ की अपेक्षा के अनुसार भारत गणराज्य अथवा जर्मन जनवादी गणराज्य अभिप्रेत है
- (ख) "कर" शब्द से विषयगत पाठ की अपेक्षा के अनुसार, भारतीय कर अथवा जर्मन जनवादी गणराज्य का अभिप्रेत है लेकिन इसमें वह राशि शामिल नहीं होगी, जो उन कर्षों, जिन पर यह करार लागू होगा, के संबंध में किन्हीं भी वृत्त अथवा गलती के लिए देय होगी अथवा जो उन कर्षों के संबंध में लगाए गए अर्थदंड की राशि होगी
- (ग) "व्यक्ति" शब्द में कोई व्यक्ति, कम्पनी और कोई अन्य गण शामिल है, जिसे संबंधित संविदाकारी राज्यों के प्रवर्तमान कराधान कानूनों के अधीन एक कर योग्य एकक के रूप में समझा जाता है

(घ) "कम्पनी" शब्द से कोई भी ऐसा निगमित निकाय अथवा अन्य गण अभिप्रेत है, जो संबंधित संविदाकारी राज्यों प्रवर्तमान कराधान कानूनों के अन्तर्गत किसी कम्पनी अथवा निगमित निकाय के रूप में माने जानी है

(ङ) "एक संविदाकारी राज्य का उद्यम" तथा "दूसरे संविदाकारी राज्य का उद्यम" शब्दों से कम्पनी एक संविदाकारी राज्य के किन्हीं निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम और दूसरे संविदाकारी राज्य के किन्हीं निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम अभिप्रेत है

(च) भारत के मामले में "सशम प्राधिकारी" शब्द से अभिप्रेत है— वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) में केन्द्र सरकार अथवा उनका प्राधिकृत प्रतिनिधि और जर्मन जनवादी गणराज्य के मामले में अभिप्रेत है—वित्त मंत्रालय;

(छ) "राष्ट्रिक" शब्द से अभिप्रेत है :—

- (i) एक संविदाकारी राज्य की, उस राज्य में प्रचलित कानूनों के अनुसार राष्ट्रिकता धारण करने वाला कोई व्यक्ति;
- (ii) कोई विधिक व्यक्ति, भागीदारी अथवा संस्था, जो संविदाकारी राज्य में प्रचलित कानूनों से प्राप्त इस प्रकार की अपनी हैसियत रखता है;

(ज) "अन्तरराष्ट्रीय यातायात" शब्दों का अभिप्राय किसी ऐसे जलयान अथवा वायुयान द्वारा किसी परिवहन से है, जो एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा संचालित किया जाता हो, सिवाय इसके कि जब उक्त जलयान अथवा वायुयान दूसरे संविदाकारी राज्य के स्थानों के बीच ही चलाया जाता है।

2. जहाँ तक किसी संविदाकारी राज्य द्वारा इस करार को लागू किए जाने का संबंध है किसी शब्द का, जो इसमें परिभाषित नहीं हुआ हो, विषयगत पाठ की अन्यथा अपेक्षा नहीं होने पर, वही अर्थ होगा जो उस राज्य में उन कर्षों से संबंधित कानूनों के प्रयोजनार्थ उसका अर्थ है, जिन पर यह करार लागू होता है।

अनुच्छेद-4

निवासी

1. इस करार के प्रयोजनों के लिए, "किसी संविदाकारी राज्य का निवासी" शब्दों से अभिप्रेत है ऐसा कोई व्यक्ति जिस पर उस राज्य के कानूनों के अन्तर्गत, उसके अधिवास, निवास प्रबन्ध-स्थान अथवा इससे मिलती-जुलती किसी अन्य कमीटी के कारण, कर लगाया जाना अपेक्षित हो।

2. जहाँ पैरा 1 के उपबंधों के कारण कोई व्यक्ति दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो, तो उसकी हैसियत निम्नानुसार निश्चित की जाएगी :—

- (क) वह उस संविदाकारी राज्य का एक निवासी माना जाएगा जिसमें उसके पास कोई स्थायी गृह हो यदि उसके पास दोनों राज्यों में कोई स्थायी निवास-गृह है, तो वह उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसके साथ उसके व्यक्तिगत और आर्थिक संबंध घनिष्ठतर हैं (महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र);
- (ख) जिस संविदाकारी राज्य में उसके महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र है, यदि उसका निश्चय नहीं किया जा सकता हो, अर्थात् उसके पास किसी भी संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी निवास-गृह नहीं हो, तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा, जिसमें उसका व्यावहारिक आवास हो;
- (ग) यदि उसका कोई व्यावहारिक आवास दोनों संविदाकारी राज्यों में है अथवा उनमें से किसी भी राज्य में नहीं है, तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा, जिसका वह राष्ट्रिक है;

(घ) यदि वह दोनों राज्यों का राष्ट्रिक है, अथवा उनमें से किसी का भी राष्ट्रिक नहीं है, तो संविदाकारी राज्यों के मक्षम प्राधिकारी परस्पर सहमति से इस प्रश्न का निर्णय करेंगे।

3. जहाँ पैराग्राफ 1 के उपबन्धों के कारण से, किसी व्यक्ति में भिन्न कोई व्यक्ति दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो, तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा, जिसमें उसकी प्रभावी प्रश्रेष्ठ व्यवस्था का स्थान स्थित है।

अनुच्छेद-5

स्थायी संस्थापन

1. इस कगार के प्रयाजना के लिए "स्थायी संस्थापन" शब्दों में कारोबार का वह एक निश्चित स्थान अर्थात् है, जहाँ से उद्यम का कारोबार पूर्णतः अथवा अंशतः चलाया जाता है।

2. "स्थायी संस्थापन" शब्दों में शिरोमण, निम्नलिखित शामिल होंगे:—

- (क) प्रवय का कोई स्थान ;
- (ख) कोई शाखा ;
- (ग) कोई कार्यालय ;
- (घ) कोई कारखाना ;
- (ङ) कोई कर्मशाला अथवा कोई भाडागार ;
- (च) कोई खान, कोई तेल अथवा गैस कुएँ, कोई खदान अथवा प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण का कोई अन्य स्थान ;
- (छ) कोई कृषि भूमि अथवा बागान ;
- (ज) बिजली के लिए अथवा आर्द्रण प्राप्त करने अथवा मांगने के लिए इस्तेमाल में लाया जा रहा कोई परिसर ;
- (झ) प्राकृतिक संसाधनों के समन्वेषण अथवा विकास के लिए इस्तेमाल में लाया जा रहा कोई प्रतिष्ठान अथवा इमारत ;
- (ञ) कोई भवन-स्थल अथवा निर्माण प्रतिष्ठान अथवा एम्बेस्सी परियोजना अथवा इनमें सम्बद्ध पर्यवेक्षण संबंधी गतिविधियों जहाँ ऐसे स्थल, परियोजना अथवा गतिविधियाँ (इन प्रकार के स्थल, परियोजनाएँ अथवा गतिविधियाँ, यदि कोई हों) छः महीने से अधिक की किसी अवधि तक कायम रहते हैं।

3. इस अनुच्छेद में पूर्ववर्ती उपबन्धों के होने हुए भी, "स्थायी संस्थापन" शब्दों में निम्नलिखित को शामिल नहीं माना जाएगा :

- (क) एक संविदाकारी राज्य की सरकार द्वारा दूसरे राज्य में निष्ठा-वित्त कोई अस्थायी भवन-स्थल अथवा निर्माण अथवा प्रतिष्ठान परियोजना ;
- (ख) उद्यम के माल अथवा पण्य के मात्र भंडारण अथवा प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ सुविधाओं का उपयोग ;
- (ग) उद्यम के माल अथवा पण्य के मात्र भंडारण अथवा प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ किसी स्टोक का रख-रखाव ;
- (घ) उद्यम के लिए माल अथवा पण्य के किसी स्टोक का किसी अन्य उद्यम द्वारा मर्यादित करने मात्र के प्रयोजनार्थ रख-रखाव ;
- (ङ) उद्यम के लिए माल अथवा पण्य का क्रय करने अथवा उसके बारे में सूचना संगृहीत करने के अन्तर्गत प्रयोजनार्थ कारोबार के किसी नियत स्थान का रख-रखाव ;
- (च) उद्यम के लिए विज्ञापन देने, सूचना देने, विज्ञापित अनुसंधानों अथवा इनसे मिली-जुलती गतिविधियाँ जो प्रारम्भिक अध्ययन गहनक किस्म की हों, के अन्तर्गत प्रयोजनार्थ, कारोबार के किसी नियत स्थान का रख-रखाव।

लेकिन उप-पैरा (ख) से (च) में के प्राधान्य उन स्थितियों में लागू नहीं होंगे जहाँ उद्यम ऊपर उप-पैराग्राफों में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न किसी प्रयोजनों के लिए दूसरे संविदाकारी राज्य में कारोबार का कोई अन्य नियत स्थान रखता हो।

4. पैराग्राफ 1 प्रीर 2 के प्राधान्यों के बावजूद जहाँ कोई व्यक्ति जो किसी स्वतंत्र हैमियन के किसी अधिकारी से भिन्न हो जिस पर पैराग्राफ 3 की व्यवस्थाएँ लागू होती हैं—एक संविदाकारी राज्य में दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की ओर से कार्य कर रहा हो तो ऐसे मामले में उस उद्यम का प्रथमस्थ राज्य में एक स्थायी संस्थापन माना जाएगा, यदि—

- (क) वह उद्यम की ओर से उस राज्य में सविदाएँ निष्पन्न करने का प्राधिकार रखता हो तथा व्यावहारिक रूप में ऐसे प्राधिकार का उपयोग करता हो जबकि उसके कार्यकालाप उस उद्यम के लिए माल अथवा पण्य के क्रय तक हो सीमित नहीं हों ;
- (ख) उसे ऐसा कोई अधिकार नहीं है लेकिन प्रथमोक्त राज्य में व्यावहारिक रूप से माल अथवा पण्य का एक ऐसा स्टोक रखता है, जिसमें से वह उस उद्यम की ओर से नियमित रूप से माल अथवा पण्य की डिलीवरी करता रहता है ; अथवा
- (ग) वह प्रथमोक्त राज्य में पूर्ण रूप से अथवा लगभग पूर्ण रूप से उसी उद्यम के लिए ही अथवा उस उद्यम पर नियंत्रण रखने वाले अथवा उस उद्यम द्वारा नियंत्रित होने वाले अथवा एक समान नियंत्रण के अधीन आने वाले उद्यम अथवा अन्य उद्यमों के लिए व्यावहारिक रूप से आर्द्र प्राप्त करता रहता है।

5. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम का दूसरे संविदाकारी राज्य में मात्र इस कारण से एक स्थायी संस्थापन नहीं माना जाएगा कि वह उस दूसरे राज्य में किसी इन्तर्गत सामान्य कर्मगत एजेंट अथवा एक स्वतंत्र हैमियन बाल किसी अन्य एजेंट के माध्यम से कारोबार करता है, बल्कि कि ऐसे व्यक्ति अपने कारोबार के काम सामान्य रूप से कर रहे हों। किन्तु, जब इस प्रकार के किसी एजेंट के कार्य-कालाप स्वयं उस उद्यम की ओर से अथवा उस उद्यम पर नियंत्रण रखने वाले अथवा उस उद्यम द्वारा नियंत्रित होने वाले अथवा एक समान नियंत्रण के अधीन आने वाले उद्यम और अन्य उद्यमों की ओर से पूर्ण रूप से किए जाते हैं तो उसे इस पैराग्राफ के अन्तिम प्राय के अन्तर्गत एक स्वतंत्र हैमियन का एजेंट नहीं माना जाएगा।

6. इस तथ्य से कि कोई कम्पनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, किसी ऐसा कम्पनी का नियंत्रण करती है अथवा उसके द्वारा नियंत्रित होती है, जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है, अथवा उस दूसरे राज्य (चाहे किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से अथवा अन्यथा) में कारोबार चलाती है, उन दोनों कम्पनियों में से कोई भी कम्पनी स्वतः दूसरी कम्पनी का एक स्थायी संस्थापन नहीं बन जाएगी।

अनुच्छेद-6

अचल सम्पत्ति से आय

1. एक संविदाकारी राज्य के निवासी की दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति (इसमें कृषि तथा वन-सम्पत्ति भी शामिल है) से अर्जित आय पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगेगा।

2. "अचल सम्पत्ति" शब्दों की परिभाषा उन संविदाकारी राज्य के कानूनों के अन्तर्गत की जाएगी, जिसमें संबंधित सम्पत्ति स्थित है। इन शब्दों में किसी भी हालत में ये शामिल होंगे—

अचल सम्पत्ति के अन्तर्गत के रूप में सम्पत्ति, कृषि और वन-सम्पत्ति में प्रयुक्त पशुवन तथा उपस्कर ऐसे अधिकार जिन पर संविदाकारी राज्य के कू-सम्पत्ति संबंधी कानूनों के उपबंध लागू होंगे हो, अचल सम्पत्ति को

भोगने के अधिकार, खनिज भण्डार, श्रौत तथा अन्य प्राकृतिक साधनों का संचालन अथवा संचालन अधिकार के प्रतिफल के रूप में परिवर्तनीय अथवा नियत अदायगियों के अधिकार।

जलयान, नौकाएं तथा वायुयान अचल सम्पत्ति नहीं माने जाएंगे।

3. पैराग्राफ 1 के उपबंध, अचल सम्पत्ति के प्रत्यक्ष उपयोग से, किए गए पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार के उपयोग से होने वाली आय पर भी लागू होंगे।

4. पैराग्राफ 1 और 3 के उपबंध किसी उद्यम की अचल सम्पत्ति से आय और स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाओं के निष्पादन के लिए इस्तेमाल में आने वाली अचल सम्पत्ति से होने वाली आय पर भी लागू होंगे।

अनुच्छेद-7

कारोबार से लाभ

1. किसी संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के लाभों पर केवल उस राज्य में ही कर लगेगा जब तक वह उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार कर रहा हो, तो उस उद्यम के लाभों पर दूसरे राज्य में कर लगेगा परन्तु केवल उतने ही लाभों पर कर लगेगा जो निम्नलिखित से प्राप्त हुए माने गए हों—(क) उस स्थायी संस्थापन; (ख) उस दूसरे राज्य में उसी प्रकार के अथवा उससे मिलते-जुलते माल अथवा पण्य की बिक्री जो उस स्थायी संस्थापन के माध्यम से बेचे जाते हैं; अथवा (ग) उस दूसरे राज्य में किए गए जैसे ही अथवा उसमें मिलते-जुलते व्यावसायिक कार्य-कलाप जैसे उस स्थायी संस्थापन के माध्यम से किए जाते हैं।

2. पैराग्राफ 3 के उपबंधों के अधधीन, जहां किसी संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है, ऐसे मामले में प्रत्येक संविदाकारी राज्य में उस स्थायी संस्थापन के कारण उसको उन लाभों का उत्पन्न होना माना जाएगा, जिनके प्राप्त होने की तब अपेक्षा रहती, जब वह समरूप अथवा मिलती-जुलती परिस्थितियों के अन्तर्गत समरूप अथवा एक समान कार्यकलापों में लगा हुआ एक निश्चित तथा अलग उद्यम होता और जिस उद्यम का वह एक स्थायी संस्थापन है। उसके साथ पूर्णतः स्वतंत्र रूप से व्यवहार करता होता। किसी भी हालत में जहां किसी स्थायी संस्थापन के कारण होने वाले सही-सही लाभों का निर्धारण किया जाना असंभव हो अथवा उसके निर्धारण करने में असाधारण कठिनाइयां उत्पन्न होती हों तो मामले में स्थायी संस्थापन के कारण होने वाले लाभ का अनुमान एक उचित आधार पर लगाया जाना चाहिए।

3. किसी स्थायी संस्थापन के लाभों के निर्धारण में व्यय की उन रकमों की कटौतियों की स्वीकृति उस राज्य के कर कानूनों के उपबंधों के अनुरूप तथा उनकी सीमाओं के भीतर रहते हुए दी जाएगी, जो स्थायी स्थापना के कारोबार के प्रयोजनों के लिए व्यय की गयी हो और उनमें इस प्रकार किए गए कार्यकारी तथा सामान्य प्रशासनिक व्यय भी शामिल रहेंगे चाहे वे उस राज्य में किए गए हों जहां स्थायी संस्थापन स्थित है अथवा अन्यत्र। तथापि, स्थायी संस्थापन द्वारा उद्यम के प्रधान कार्यालय को अथवा उसके अन्य कार्यालयों में से किसी कार्यालय को पेटेंटों, तकनीकी जानकारी अथवा अन्य अधिकारों के प्रयोग के बचने में रायल्टियों, फीस अथवा इससे मिलती-जुलती अन्य अदायगियों के रूप में अथवा विशिष्ट सेवासम्पादन के लिए अथवा प्रबंध के लिए कमीशन अथवा प्रभारों के रूप में अथवा किसी बैंक उद्यम के मामलों को छोड़कर स्थायी संस्थापन को उधार दिए गए धन पर ब्याज के रूप में, यदि कोई रकम (वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति से भिन्न रूप में) अदा की गयी हो, तो उनके संबंध में ऐसी किसी कटौती की स्वीकृति नहीं दी जाएगी। इसी प्रकार स्थायी संस्थापन के लोगों के निर्धारण में उन रकमों का हिसाब नहीं लिया जाएगा जो स्थायी संस्थापन द्वारा उद्यम के प्रधान कार्यालय को अथवा

उसके अन्य कार्यालयों में से किसी कार्यालय की पेटेंटों, तकनीकी जानकारी अथवा अन्य अधिकारों के प्रयोग के बचने में रायल्टियों, फीस अथवा इससे मिलती-जुलती अन्य अदायगियों के रूप में अथवा विशिष्ट सेवा सम्पादन के लिए अथवा प्रबंध के लिए कमीशन अथवा प्रभारों के रूप में अथवा किसी बैंक उद्यम के मामले को छोड़कर प्रधान कार्यालय को अथवा उसके अन्य कार्यालयों में से किसी को उधार दिए गए धन पर ब्याज के रूप (वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति से भिन्न रूप में) में प्रभारित की गयी हो।

4. कोई लाभ केवल इस कारण किसी स्थायी संस्थापन को हुए नहीं माने जायेंगे कि उस स्थायी संस्थापन द्वारा उद्यम के लिए माल अथवा पण्य खरीदी गयी है।

5. पूर्ववर्ती पैराग्राफ के प्रयोजन के लिए, स्थायी संस्थापन के कारण माने जाने वाले लाभों को तब तक उम्मीदवत्ति से वर्षानुवर्ष निर्धारित किया जाएगा, जब तक कि उसके विरुद्ध कोई उपयुक्त तथा पर्याप्त कारण नहीं हों।

6. जहां लाभों में आय की वे मद्धे भी शामिल हों, जिनका विवेचन इस करार के अन्य अनुच्छेदों में अलग से किया गया है, ऐसे मामलों में उन अनुच्छेदों के उपबंध इस अनुच्छेद के उपबंधों से प्रभावित नहीं होंगे।

अनुच्छेद-8

वायु परिवहन

1. किसी संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में विमान-संचालन से प्राप्त लाभों पर कर उस संविदाकारी राज्य में ही लगेगा।

2. किसी पूल, किसी संयुक्त कारोबार अथवा अन्तरराष्ट्रीय परिचालन अधिकरण में भागीदारी से प्राप्त लाभों पर भी पैरा 1 के प्रावधान लागू होंगे।

3. इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए अन्तरराष्ट्रीय यातायात में विमान-संचालन से संबंधित निधियों पर ब्याज को ऐसे विमान के संचालन से प्राप्त लाभ के रूप में समझा जाएगा और अनुच्छेद 12 के उपबंध इस प्रकार के ब्याज के संबंध में लागू नहीं होंगे।

4. "विमान के संचालन" शब्दों से यात्रियों, डाक, पशुधन के हवाई जहाज से परिवहन संबंधी कारोबार अथवा वायुयान के स्वामी अथवा पट्टेदारों अथवा अवक्रेता द्वारा मान को ले जाना अभिप्रेत है, जिसमें अन्य उद्यमों की ओर से ऐसे परिवहन के लिए टिकटों की बिक्री करना, वायुयान को आकस्मिक पट्टे पर देना तथा ऐसे परिवहन से सीधे संबंधित अन्य कार्यकलाप करना भी शामिल है।

अनुच्छेद-9

जहाजरानी

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयान परिवहन से हुई आय पर दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगेगा।

2. भारतीय जलयानों द्वारा तथा दोनों राज्यों के पत्तनों के बीच समय भाड़े पर चलने वाले जलयानों द्वारा ले जाये जाने वाले राष्ट्रीय माल के भाड़े से प्राप्त आय और/अथवा लाभों पर जर्मन जनशक्ति गणराज्य की सरकार द्वारा बिना प्रकार का आयकर और/अथवा आमदनी कर लगाया गया अथवा जर्मन जनशक्ति गणराज्य की सरकार द्वारा जर्मन जलयानों तथा दोनों राज्यों के पत्तनों के बीच समय भाड़े पर चलने वाले जलयानों द्वारा ले जाये जाने वाले राष्ट्रीय माल के भाड़े से प्राप्त

आय और/अथवा लाभों पर भारत गणराज्य की सरकार द्वारा किन्हीं प्रकार का आयकर और/अथवा आमदनी कर को लगाया अथवा वसूल नहीं किया जाएगा।

3. दोनों संविदाकारी राज्यों के मान से भिन्न किसी मान के परिचालन के लिए अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जहाजों के परिचालन से एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम को प्राप्त आय पर दूसरे संविदाकारी राज्य में भी कर लगेगा लेकिन इस प्रकार के कर की मात्रा सीत-वैश में अन्यथा उद्घुष्टनीय कर के 50 प्रतिशत तक सीमित होगी।

4. इस अनुच्छेद के उपबंध जलधानों के संचालन के लिए किसी पूत, किंवा संयुक्त कारोबार अथवा किसी प्रकार की अन्तरराष्ट्रीय एजेंसी में भाग लेने से होने वाले लाभों के संबंध में भी लागू होंगे।

5. इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए :

- (क) अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलधानों के संचालन से संबंधित विधियों पर ब्याज को इस प्रकार के जलधानों के संचालन से प्राप्त आय के रूप में समझा जाएगा और अनुच्छेद 12 के उपबंध इस प्रकार के ब्याज के संबंध में लागू नहीं होंगे; और
- (ख) जलधानों के संचालन से प्राप्त आय में, अन्तरराष्ट्रीय यातायात में मान तथा पण्य के परिचालन के संबंध में आधानों (इनमें ट्रेजरी तथा आधानों के परिचालन से संबंधित उपस्कर भी शामिल हैं) के इस्तेमाल रख-रखाव अथवा उन्हें किराए पर दिए जाने से प्राप्त आय भी शामिल है।

अनुच्छेद 10

सम्बद्ध उद्यम

जहाँ :—

- (क) एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में किसी उद्यम के प्रबंध, नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेता है, अथवा
- (ख) वहाँ व्यक्ति, प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम में और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम में प्रबंध, नियंत्रण अथवा पूंजी में भाग लेता है,

और दोनों में से किसी भी अवस्था में दोनों उद्यमों के बीच उनके वाणि-ज्यिक अथवा वित्तीय संबंधों में ऐसी शर्तें रखा जाती हैं अथवा लगाई जाती हैं, जो उन शर्तों से भिन्न हैं, जैसी स्वतंत्र उद्यमों के बीच रखा जाती हैं, ऐसे मामले में ऐसे कोई लाभ जो, उन शर्तों के नहीं होने का हालत में उन उद्यमों में से किसी एक उद्यम को प्राप्त हुए होते, किन्तु उन शर्तों के कारण प्राप्त नहीं हुए तो वे लाभ उस उद्यम के लाभों में सम्मिलित किए जायेंगे और वे नवतुसार करायेय होंगे।

अनुच्छेद 11

लाभांश

1. जो कम्पनी एक संविदाकारी राज्य की निवासी हो, उसके द्वारा पू. दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए गए लाभांश उस दूसरे राज्य में करायेय होंगे।

2. तथापि, इस प्रकार के लाभांश उस संविदाकारी राज्य में भी करायेय होंगे, जिसकी लाभांश अदा करने वाली कम्पनी और कर राज्य के कानूनों के अनुसार होंगे, लेकिन यदि प्राप्तकर्ता लाभांशों का लाभभोगी स्वामी है तो इस प्रकार प्रसारित कर निम्नलिखित से अधिक नहीं होना चाहिए :

- (क) लाभांश की सराफ राशि का 15 प्रतिशत, यदि लाभभोगी स्वामी एक कम्पनी है और जो लाभांश अदा करने वाली कम्पनी में कम से कम 25 प्रतिशत शेयर रखती है,

(ख) अन्य सभी मामलों में लाभांश की सराफ राशि का 25 प्रतिशत। इस पैराग्राफ से कम्पनी के उन लाभों, जिनसे लाभांशों की अदायगी की जाती है, के कराधान के संबंध में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

3. इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त "लाभांशो गन्ध का अधिप्राय ऐसे शेयरों अथवा अन्य अधिकारों से, जो ऋण दावे नहीं हैं और लाभों के सहयोगी हैं, प्राप्त आय से तथा अन्य निर्गमित अधिकारों से प्राप्त आय से है जिस पर उस संविदाकारी राज्य के कानूनों द्वारा शेयरों से प्राप्त आय पर लगाए जाने वाले कर के अनुसार ही कर लगाया जाता है, जिसकी बितरण करने वाली कम्पनी एक निवासी है।

4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि लाभांशों का हितभागी स्वामी, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य में वहाँ स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से व्यापार करता है, जिसकी लाभांश अदा करने वाली कम्पनी निवासी है अथवा उसने दूसरे राज्य में स्थित किसी नियत स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं प्रदान करता है, और जिस धारिता के बारे में लाभांशों की अदायगी की जाती है, वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा नियत स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध है। ऐसे मामले में, अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 15 के उपबंध, जैसे भी पस्ति हो लागू होंगे।

5. जहाँ कोई कम्पनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य से लाभ अथवा आय प्राप्त करती है, वहाँ उस कम्पनी द्वारा अदा किए गए लाभांशों पर, जहाँ तक कि ऐसे लाभांशों को छोड़कर जो दूसरे राज्य के किसी निवासी को अदा किए गए हो अथवा जहाँ तक कि ऐसी धारिता के बारे में लाभांशों की अदायगी की जाती है, जो उस राज्य में स्थित इस प्रकार के किसी स्थायी संस्थापन अथवा नियत स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध है उस दूसरे राज्य में न तो कोई कर लगाया जाएगा और न ही कम्पनी के अवितरित लाभों पर अवितरित लाभकर की किस्म का कोई कर लगाया जाएगा, चाहे अदा किए गए लाभांश अथवा अवितरित लाभ पूर्णतः अथवा अंशतः उस दूसरे राज्य में उत्पन्न होने वाले लाभ अथवा आय के रूप में ही हों।

अनुच्छेद 12

ब्याज

1. एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाले तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए जाने वाले ब्याज पर उस दूसरे राज्य में कर लगेगा।

2. तथापि, इस प्रकार के ब्याज पर उस संविदाकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगेगा जिस राज्य में यह उद्भूत होता है किन्तु यदि प्राप्तकर्ता ब्याज का हितभागी स्वामी ही तो इस प्रकार प्रसारित कर की राशि ब्याज की सराफ राशि के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

पैराग्राफ 2 के उपबंधों के बावजूद,

(क) एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाले ब्याज पर उस राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी यदि यह निम्नलिखित द्वारा प्राप्त किया गया हो तथा लाभ धारित हो :

- (i) दूसरे संविदाकारी राज्य की सरकार, कोई राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा कोई स्थानीय प्राधिकरण, अथवा
- (ii) दूसरे संविदाकारी राज्य का सेंट्रल बैंक,

(ख) किसी संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाले ब्याज पर उक्त संविदाकारी राज्य में उस राज्य की सरकार द्वारा अनुमोदित सीमा तक कर में छूट हो जाएगी, यदि वह ब्याज उप-पैरा (क) में उल्लिखित किसी व्यक्ति से भिन्न उस अन्य व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया गया हो और लाभ के लिए धारित हो, जो

दूसरे संविदाकारी राज्य का एक निवासी है, वशर्त कि प्रथमोक्त संविदाकारी राज्य की सरकार द्वारा इस संबंध में ऋण दावे के लिए लेन-देन के मामले को अनुमोदित किया गया हो।

4. इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त "व्याज" शब्द का अभिप्राय सभी प्रकार के ऋण-दावों से प्राप्त आय से है, चाहे वह बन्धक के रूप में आरक्षित रखी गई हो अथवा नहीं रखी गई हो और चाहे उसके बारे में कर्जदार के लाभों में भागीदारी का अधिकार प्राप्त हो अथवा नहीं प्राप्त हो, और विशेषतः सरकारी प्रतिभूतियों से प्राप्त होने वाली आय और बंध पत्रों अथवा ऋण पत्रों से प्राप्त होने वाली आय, जिसमें ऐसी प्रतिभूतियों, बन्धपत्रों अथवा ऋण पत्रों के साथ जुड़े हुए लाभ तथा पुरस्कार से, प्राप्त आय भी शामिल है। देर से की गई अदायगी के लिए लगाए गए अर्थ-दण्ड को इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ व्याज के रूप में नहीं माना जाएगा।

5. पैराग्राफ 1 और 2 के संबंध में उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि व्याज का हितभागी स्वामी एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के कारण दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसमें व्याज उत्पन्न हुआ हो, उसमें स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार चलाता हो अथवा उस दूसरे राज्य में स्थित किसी नियत स्थान के स्वतंत्र रूप से वैयक्तिक सेवाएं प्रदान करता हो और जिस ऋण दावे के बारे में व्याज अदा किया गया हो वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा नियत स्थान से प्रभाव रूप से संबंधित हो। इस प्रकार के मामले में अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 15 के उपबंध, जैसा भी मामला हो, लागू होंगे।

6. किसी संविदाकारी राज्य में उस स्थिति में व्याज उद्भूत हुआ माना जाएगा, यदि व्याज अदा करने वाला स्वयं वह संविदाकारी राज्य, कोई राजनैतिक उप प्रभाग, कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा उक्त राज्य का कोई निवासी हो। किन्तु जहाँ व्याज अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह किसी संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं हो, संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी संस्थापन है अथवा ऐसा कोई नियत स्थान है, जिसके संबंध में वह ऋण लिया गया था और जिस पर व्याज की अदायगी की गई हो और इस प्रकार का व्याज उस स्थायी संस्थापन अथवा नियत स्थान द्वारा वहन किया जाता है तब वह व्याज उस संविदाकारी राज्य में उद्भूत माना जाएगा, जिसमें उक्त स्थायी संस्थापन अथवा नियत स्थान स्थित है।

7. जहाँ व्याज अदा करने वाले अथवा लाभभोगी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों में तथा और किसी दूसरे व्यक्ति के बीच विशेष प्रकार का कोई संबंध होने के कारण, व्याज की रकम, उस ऋण दावे को ध्यान में रखते हुए, जिसके लिए व्याज की रकम अदा की गई है, व्याज की उस रकम से बढ़ जाती है जिसके लिए इस प्रकार के संबंध में नहीं होने की स्थिति में व्याज अदा करने वाले और हितभागी स्वामी के बीच सहमति हुई होती, तो ऐसे मामले में इस अनुच्छेद के उपबंध अंतिम वर्णित रकम पर लागू होंगे। इस प्रकार के मामले में अदायगी के अतिरिक्त भाग पर, इस अनुच्छेद के अन्य उपबंधों को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगेगा।

अनुच्छेद 13

रायल्टियाँ और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस

1. एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाली और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा की गई रायल्टियाँ और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर उस दूसरे राज्य में कर लगेगा।

2. तथापि, ऐसी रायल्टियों और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर उस संविदाकारी राज्य में भी जिसमें वे उद्भूत होती हैं और उसी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगेगा, किन्तु यदि प्राकृतिक रायल्टी या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस का हितभागी स्वामी हो तो इस प्रकार लगाया गया कर ऐसी रायल्टियों या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की उक्त रकम के 22.5 (माइ बीईस) प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

3. इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त "रायल्टियाँ" शब्द से साहित्यिक, कलात्मक अथवा वैज्ञानिक कृतियों, जिनमें रेडियो अथवा दूरदर्शन से प्रसारण के लिए प्रयुक्त किये जाने वाली चलचित्र, फिल्में अथवा टेपें शामिल हैं, कोई गेटेट, ट्रेड मर्क, डिजाइन तथा मॉडल, प्लान, गुप्त फार्मूला अथवा प्रक्रिया के प्रयोग अथवा प्रयोगाधिकार के एक प्रतिफल के रूप में अथवा औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक उपस्कर के प्रयोग के लिए अथवा प्रयोगाधिकार के लिए अथवा औद्योगिक वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक अनुभव से संबंधित जानकारी के लिए प्राप्त किसी प्रकार की अदायगी अभिप्रेत है।

4. इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त "तकनीकी सेवाओं के लिए फीस" पद से किसी प्रबन्धकीय, तकनीकी अथवा परामर्शदायी स्वरूप की सेवाओं के प्रतिफल में, जिसमें तकनीकी अथवा अन्य कामियों की सेवाओं की व्यवस्था भी शामिल है, अदायगी करने वाले किसी व्यक्ति के किसी कर्मचारी को की जाने वाला अदायगियों से भिन्न कितने व्यक्ति को कितने प्रकार की रकम की अदायगियाँ अभिप्रेत हैं।

5. पैराग्राफ 1 और 2 के संबंध में उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि रायल्टियाँ अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस का हितभागी स्वामी, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य में वहाँ स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है जिसमें रायल्टियाँ अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उद्भूत होती है या वहाँ स्थित किसी निश्चित स्थान से उस दूसरे राज्य में स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निष्पादित करता है और जिस अधिकार या सम्पत्ति अथवा संविदा के संबंध में रायल्टियाँ या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा की जाती है, वह ऐसे स्थायी संस्थापन या निश्चित स्थान से प्रभाव रूप से संबंधित है। ऐसे मामले में, अनुच्छेद 7 या अनुच्छेद 15 के उपबंध, जैसा भी स्थिति हो, लागू होंगे।

6. रायल्टियों और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुई माना जाएगा जब अदा करने वाला स्वयं वह राज्य, उस राज्य का कोई राजनैतिक उप प्रभाग, कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा उस राज्य का कोई निवासी हो। परन्तु, जहाँ रायल्टियाँ अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा करने वाले व्यक्ति को, चाहे वह किसी संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं हो, किसी संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी संस्थापन अथवा कोई निश्चित स्थान हो जिसके संबंध में रायल्टियाँ अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की अदायगी का दायित्व उत्पन्न था और ऐसी रायल्टियाँ अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस ऐसे स्थायी संस्थापन या निश्चित स्थान द्वारा वहन की जाती है तब ऐसी रायल्टियाँ अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उस राज्य में उद्भूत हुई माना जाएगा जिसमें स्थायी संस्थापन या निश्चित स्थान स्थित है।

7. जहाँ अदाकर्ता और हितभागी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों तथा और किसी दूसरे व्यक्ति के बीच विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण रायल्टियाँ अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस का रकम, उस रकम से जो ऐसे संबंध के न होने पर अदा की गई होती, बढ़ जाता है तो वहाँ इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अंतिम वर्णित रकम पर ही लागू होंगे। ऐसे मामले में अधिक अदा की गई रकम पर इस प्रकार के अन्य उपबंधों पर यथोचित ध्यान देते हुए प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगेगा।

अनुच्छेद 14

पूर्ण गन्त. अधिलेख

1. एक संविदाकारी राज्य को किसी निवासी का अनुच्छेद 6 में उल्लिखित तथा दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अथवा सम्पत्ति के अन्तर्गत से प्राप्त होने वाले अतिरिक्त भाग पर उस दूसरे राज्य में कर लगेगा।

2. जब सम्पत्ति के शस्त्रण के लिए अधिलेखों पर, जो एक संविदाकारी राज्य के किसी स्थायी संस्थापन की व्यापारिक सम्पत्ति के

राज्य के रूप में दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित है अथवा जो एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की मरणांश उत्तराधिकारियों के अंगण दा के प्रयोजनार्थ दूसरे संविदाकारी राज्य में उपलब्ध किया निश्चित स्थान में संबंधित बल संपादित हो, जिनमें ऐसे स्थायी सम्पत्ति (यहोत अथवा सम्पूर्ण उद्यम के साथ) अथवा ऐसे निश्चित स्थान के अन्तर्गत में होने वाले ऐसे प्रतिस्पर्ध भाग शामिल हैं, उस दूसरे राज्य में कर लगेगा।

3. अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा या में चलने वाले जहाजों अथवा वायुयानों अथवा ऐसे जहाजों अथवा वायुयानों के साथ या में संबंधित बल संपादित के अन्तर्गत में प्राप्त होने वाले अभिवाधा पर करण उस संविदाकारी राज्य में कर लगेगा जिसका कि अन्तराष्ट्रिकता निवास है।

4. किसी ऐसे कम्पनी के पुंजीयन स्थाप के शेयरों के अन्तर्गत में प्राप्त होने वाले अभिवाधा पर, किसी सम्पत्ति प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रधानता किंवा संविदाकारी राज्य में स्थित अथवा संपादित हो, उस राज्य में कर लगेगा।

5. पैराग्राफ 4 में उल्लिखित शेयरों में भिन्न शेयरों के किसी ऐसे कम्पनी में, अन्तर्गत में होने वाले अभिवाधा पर, जो किता संविदाकारी राज्य की निवासी है उस राज्य में कर लगेगा।

6. पैराग्राफ 1, 2, 3, 4 तथा 5 में उल्लिखित संपत्ति से भिन्न किन्तु संपत्ति के अन्तर्गत में प्राप्त होने वाले अभिवाधा पर केवल उस संविदाकारी राज्य में कर लगेगा जिसका कि अन्तराष्ट्रिकता एक निवास है।

अनुच्छेद 15

स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं

1. किसी व्यष्टि द्वारा, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है, व्यावसायिक सेवाओं अथवा उससे मिलने-जुलने स्वरूप के दूसरे स्वतंत्र कार्यकर्ताओं के निष्पादन में प्राप्त की जाने वाली आय निम्नलिखित परिस्थितियों को छोड़कर जब ऐसे आय पर दूसरे संविदाकारी राज्य में भी कर लगेगा, केवल उस राज्य में कर लगेगा।

(क) यदि उस अपने कार्यकर्ताओं के निष्पादन के प्रयोजनार्थ दूसरे संविदाकारी राज्य में कोई निश्चित स्थान नियमित रूप में उपलब्ध है, तो उस मामले में, उस दूसरे राज्य में आय की उत्तरी रकम पर कर लगेगा जो उस निश्चित स्थान के कारण उद्भूत हुई सार्वा आ सकनी है, अथवा

(ख) यदि दूसरे संविदाकारी राज्य में ठहरने की उसकी अधि अथवा अधधिया संगत "विगत वर्ष" अथवा "आयवर्ष" में, जैसी भी स्थिति हो, कुल 90 दिन अथवा उसमें अधिक हो, तो उस मामले में, आय के केवल उतने ही भाग पर उस दूसरे राज्य में कर लगेगा जो उस दूसरे राज्य में निष्पादित उसके कार्य-कलाओं से प्राप्त हुई हो।

2. "व्यावसायिक सेवाएं" पद में स्वतंत्र वैज्ञानिक, साहित्यिक, कलात्मक, शैक्षणिक अथवा अध्यापन संबंधी कार्य-कलाप तथा चिकित्सकों, अन्य चिकित्सकों, वकीलों, इंजीनियरों, वास्तुविदों, दंत-चिकित्सकों तथा केजापलों के स्वतंत्र कार्य कलाप शामिल है।

अनुच्छेद 16

पराश्रित वैयक्तिक सेवाएं

1. अनुच्छेद 17, 18, 19, 20, 21 तथा 22 के उपबंधों के अधधीन रहते हुए, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त वेतन, मजूदरी तथा इसी प्रकार के दूसरे पारिश्रमिक पर केवल उसी राज्य में कर लगेगा जब तक कि उसका नियोजन दूसरे संविदाकारी राज्य में नहीं किया जाता है। यदि इस प्रकार नियोजन किया जाता है तो ऐसे पारिश्रमिक पर, जो उसमें प्राप्त होता है, उस दूसरे राज्य में कर लगेगा।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होने हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर केवल प्राचीनस्थित राज्य में ही कर लगेगा, यदि :

(क) पारिश्रमिक, प्राप्तकर्ता संगत "वित्तीय वर्ष" में, जैसी भी स्थिति हो। कुल मिलाकर 183 दिन में अधिक अथवा अधधियों के लिए दूसरे राज्य में मौजूद रहा हो, तथा

(ख) पारिश्रमिक की आयगी ऐसे नियोजक द्वारा अथवा उसकी ओर से की जाती है जो उस दूसरे राज्य का निवासी नहीं है, तथा

(ग) पारिश्रमिक किसी ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा किसी निश्चित स्थान द्वारा वसूल नहीं किया जाता है जो नियोजक का दूसरे राज्य में है।

3. इस अनुच्छेद के उपबंधों के होने हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में किसी शैलान अथवा किसी वायुयान के परिचालन के संबंध में किए गए नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर उसी राज्य में कर लगेगा।

4. भारत और जर्मन जनवादी गणराज्य के बीच वैज्ञानिक विचारों के आदान-प्रदान एवं सहयोग के लिए समय समय पर प्रवृत्त करारों के अधीन दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी भी संविदाकारी राज्य के विशेषज्ञों को दूसरे संविदाकारी राज्य में भेजने पर उन्हें उनके संबंधित राज्यों द्वारा उन्हें अदा किए गए वेतनों तथा भत्तों पर आय कर की अवधायी किए जाने से उस दूसरे राज्य द्वारा छूट दी जाएगी।

अनुच्छेद 17

निवेशकों की फीस तथा उच्च स्तरीय प्रबंधकीय अधिकारियों का पारिश्रमिक

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी ऐसे कम्पनी के निदेशक-मण्डल के एक सदस्य की हैमियत में जो दूसरे संविदाकारी राज्य के एक निवासी है, प्राप्त निवेशक की फीस तथा उससे मिलती जुलती किस्म की अदायगियों पर कर उस दूसरे राज्य में लगेगा।

2. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा, किसी ऐसे कम्पनी के, जो दूसरे राज्य के एक निवासी है, उच्चस्तरीय प्रबंधकीय पद पर नियुक्त एक कर्मचारी की हैमियत में प्राप्त वेतन, मजूदरी तथा इससे मिलने जुलने अन्य पारिश्रमिक पर उस दूसरे राज्य में कर लगेगा।

अनुच्छेद 18

मनोरंजनकर्ताओं द्वारा अर्जित आय

अनुच्छेद 15 तथा 16 के उपबंधों के होने हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा एक मनोरंजनकर्ता के रूप में, जैसे कि, थियेटर, चलचित्र, रेडियो अथवा दूरदर्शन कलाकार अथवा संगीतकार के रूप में अपने व्यक्तिगत कार्यक्रमों में, जिनमें उसने दूसरे संविदाकारी राज्य में सम्पन्न किया है, प्राप्त आय पर कर उस दूसरे राज्य में लगेगा।

बशर्त कि व्यष्टियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा, विपक्षीय अथवा बहुपक्षीय आधार पर संविदाकारी राज्यों के बीच तब किए गए सांस्कृतिक आदान-प्रदान के ढांच के अंतर्गत किए गए कार्यक्रमों से प्राप्त आय पर केवल उसी राज्य में कर लगेगा जिसके कि वे निवासी हैं।

अनुच्छेद 19

सरकारी सेवा के संबंध में पारिश्रमिक तथा पेंशन

1. (क) एक संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उपमण्डल अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी व्यष्टि को उस

राज्य अथवा उसके उपमण्डल अथवा प्राधिकरण के लिए की गई सेवाओं के संबंध में प्रवृत्त किसी पेंशन से भिन्न पारिश्रमिक केवल उसी राज्य में कराधेय होगा।

(ख) लेकिन ऐसा पारिश्रमिक केवल उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कराधेय होगा यदि सेवाएं उस दूसरे राज्य में की जाती हैं तथा वह व्यक्ति उस राज्य का एक निवासी है जो :

(i) उस राज्य का एक राष्ट्रिक है, अथवा

(ii) केवल सेवाएं प्रदान करने के प्रयोजनार्थ उस राज्य का एक निवासी नहीं बना था।

2. (क) किसी संविदाकारी राज्य द्वारा अथवा उसके किसी राजनैतिक उपमण्डल अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा सृजित किए गए कोष द्वारा अथवा उसमें से किसी व्यक्ति को उसके द्वारा उस राज्य अथवा उपमण्डल अथवा प्राधिकरण के लिए की गई सेवाओं के लिए प्रदान कोई पेंशन केवल उसी राज्य में कराधेय होगी।

(ख) लेकिन ऐसी पेंशन दूसरे संविदाकारी राज्य में केवल तभी कराधेय होगी यदि वह व्यक्ति उस दूसरे राज्य का एक निवासी तथा एक राष्ट्रिक हो।

3. अनुच्छेद 16, 17 तथा 18 के उपबन्ध किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उपमण्डल अथवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा चलाये गये किसी कारोबार क सिलसिले में की गयी सेवाओं के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक तथा पेंशनों पर लागू होंगी।

अनुच्छेद 20

रीर-सरकारी पेंशन तथा वाषिकी

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के स्रोतों से प्राप्त अनुच्छेद 19 में उल्लिखित किसी पेंशन से भिन्न किसी पेंशन अथवा किसी वाषिकी पर कर प्रथमोलिखित संविदाकारी राज्य में लगेगा।

2. "पेंशन" शब्द से पिछली सेवाओं के लिए प्रतिकूल के रूप में अथवा सेवाओं के निष्पादन के दौरान हुई क्षतियों के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में की जाने वाली आवधिक अदायगी अभिप्रेत है।

3. "वाषिकी" शब्द से जीवन काल में अथवा किसी निश्चित या निश्चय समयावधि के दौरान धन-राशि अथवा उसके बराबर मूल्य में पर्याप्त तथा पूर्ण प्रतिकूल की अदायगी करने के इकरार के अन्तर्गत आवधिक रूप में निश्चित समय पर अदायगी योग्य एक निश्चित राशि अभिप्रेत है।

अनुच्छेद 21

विद्यार्थियों तथा प्रशिक्षुओं द्वारा प्राप्त अदायगियां

1. किसी विद्यार्थी अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षु को, जो दूसरे संविदाकारी राज्य का दौरा करने से तत्काल पहले संविदाकारी राज्यों में से किसी एक का निवासी है अथवा था तथा वह दूसरे राज्य में केवल अपनी शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ उपस्थित है, दूसरे संविदाकारी राज्य में निम्नलिखित पर कर से छूट प्राप्त होगी :

(क) उस दूसरे संविदाकारी राज्य के बाहर रहने वाले व्यक्तियों द्वारा उसके भरण-पोषण, शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ उसे की गयी अदायगियां, तथा

(ख) उस दूसरे संविदाकारी राज्य में किसी "विगत वर्ष" अथवा "प्राय वर्ष" में जैसी भी स्थिति हो, रोजगार से प्राप्त पारिश्रमिक पर, जो 15,000 रु अथवा जमाने अनुसार गणराज्य

के "मार्क" में उसके समतुल्य से अनधिक हो, वहां कि ऐसा नियोजन उसके अध्ययन से सीधे संबंधित हो अथवा उसके भरण-पोषण के प्रयोजनार्थ किया गया हो।

2. इस अनुच्छेद का लाभ केवल ऐसी अवधि के लिए मिलेगा जो शुरू की गयी शिक्षा अथवा प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए उचित अथवा साधारणतया अपेक्षित हो, परन्तु किसी भी हानत में किसी व्यक्ति को उस दूसरे संविदाकारी राज्य में प्रथम बार उसके पहुँचने की तारीख से लगातार छः वर्षों से अधिक अवधि के लिए इस अनुच्छेद का लाभ प्राप्त नहीं होगा।

अनुच्छेद 22

प्राध्यापकों, अध्यापकों तथा शोधितमूर्धों द्वारा प्राप्त अदायगियां

1. किसी प्राध्यापक अथवा अध्यापक को, जो उस दूसरे संविदाकारी राज्य में किसी विश्वविद्यालय में, कालेज में, विद्यालय में अथवा दूसरी मान्यता प्राप्त संस्था में अध्यापन अथवा शोध-कार्य के लिए अथवा दोनों के प्रयोजनार्थ दूसरे संविदाकारी राज्य का दौरा करने से तत्काल पहले संविदाकारी राज्यों में से किसी एक का निवासी है अथवा था, उस दूसरे राज्य में पहुँचने की तारीख से दो वर्षों से अधिक की अवधि के लिए ऐसे अध्यापन अथवा शोध कार्य के लिए प्राप्त किसी पारिश्रमिक पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी।

2. यह अनुच्छेद उस शोध कार्य से प्राप्त आय पर लागू नहीं होगा, यदि ऐसा शोधकार्य मूलतः किसी व्यक्ति विशेष अथवा व्यक्तियों के निजी लाभ के लिए किया जाता है।

3. इस अनुच्छेद तथा अनुच्छेद 21 के प्रयोजनार्थ किसी व्यक्ति को एक संविदाकारी राज्य का निवासी समझा जाएगा यदि वह "विगत वर्ष" अथवा "प्राय वर्ष" में जैसी भी स्थिति हो, उस संविदाकारी राज्य का निवासी हो जिनमें "विगत वर्ष"/"प्राय वर्ष" के तत्काल पूर्व वह दूसरे संविदाकारी राज्य का दौरा करता है।

4. पैराग्राफ 1 के प्रयोजनार्थ "मान्यता प्राप्त संस्था" का अर्थ एक ऐसी संस्था से है जिसे हम संबंध में संबंधित संविदाकारी राज्य के तत्काल प्राधिकारी द्वारा मान्यता दी गयी है।

अनुच्छेद 23

अन्य आय

1. पैराग्राफ 3 के उपबन्धों के अधीन रहने हुए, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की आय की ऐसी मदों, जहाँ कहीं वे उद्भूत होती हैं और जिन पर इस करार के पूर्वोक्त अनुच्छेदों में स्पष्ट रूप से विचार नहीं किया गया है, केवल उस संविदाकारी राज्य में कराधेय होगी।

2. पैराग्राफ 1 के उपबन्ध अनुच्छेद 6 के पैराग्राफ 2 में यथापरिभाषित अन्तर्गत से प्राप्त आय से भिन्न आय पर लागू नहीं होंगे, यदि ऐसी आय का प्राप्तकर्ता एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के बाद, दूसरे संविदाकारी राज्य में, वहाँ स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कार्रवाही करता है अथवा उस दूसरे राज्य में वहाँ स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निष्पादित करता है, तथा ऐसा अधिकार अथवा सम्पत्ति जिसके संबंध में ऐसी आय अदा की जाती है, ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित आधार के प्रभावी से संबंध है। ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 15 के उपबन्ध, स्थिति हो, लागू होंगे।

3. पैराग्राफ 1 तथा 3 के उपबन्धों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के निवासी की आय की ऐसी मदों पर भी, जिन पर इस करार के पूर्वोक्त अनुच्छेदों में विचार नहीं किया गया है तथा जो दूसरे संविदाकारी राज्य में उद्भूत होती हैं, उस दूसरे राज्य में कर लगता।

अनुच्छेद 24

पूँजी

1. अनुच्छेद 6 में उल्लिखित अंश संपत्ति द्वारा निरूपित पूँजी पर जो एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी के स्वामित्व में हो तथा दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित हो, उस दूसरे राज्य में कम लागू होगा।

2. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन की कारोबार संपत्ति के अंक रूप में बल सम्पत्ति द्वारा अथवा किसी निश्चित स्थान से संबंधित ऐसी बल संपत्ति द्वारा जो एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को दूसरे संविदाकारी राज्य में स्वतंत्र व्यक्तिक सेवाओं के निष्पादन के प्रयोजनार्थ उपलब्ध है, निरूपित पूँजी पर उस दूसरे राज्य में कर लगेगा।

3. अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में लाने जाने वाले जलयानों अथवा वायुयानों द्वारा और ऐसे जलयानों अथवा वायुयानों के गंतव्य से संबंधित बल सम्पत्ति द्वारा निरूपित पूँजी केवल उस संविदाकारी राज्य में ही कराधेय होगी जिसका कि ऐसी संपत्ति का स्वामी उद्यम एक निवासी है।

4. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की पूँजी के अन्य सभी तत्वों पर दोनों संविदाकारी राज्यों में कर लगेगा।

अनुच्छेद 25

दोहरे कराधान का निरसन

1. दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी भी राज्य में प्रवृत्त कानून संबंधित संविदाकारी राज्य में आय और पूँजी के कराधान के मामलों में लागू रहेंगे लेकिन ऐसे मामलों को छोड़कर जहाँ पर इस करार में उनके विपरीत कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया जाता है।

2. जहाँ एक संविदाकारी राज्य का कोई निवासी ऐसी आय प्राप्त करता है अथवा पूँजी का स्वामित्व रखता है जिस पर इस करार के उपबंधों के अनुसार दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकता है, वहाँ प्रभावोन्निहित राज्य पैराग्राफ 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए ऐसी आय अथवा पूँजी को कर में छूट प्रदान करेगा।

3. जहाँ इस करार के किसी उपबन्ध के अनुसार एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा प्राप्त आय अथवा स्वामित्व वाली पूँजी को उस राज्य में कर से छूट प्राप्त है तो फिर भी ऐसी आय, ऐसे निवासी की शेष आय अथवा पूँजी पर कर की रकम की संगणना करने समय, इस प्रकार छूट प्राप्त आय अथवा पूँजी को हिसाब में रखेगा।

अनुच्छेद 26

सम व्यवहार

1. एक संविदाकारी राज्य के राष्ट्रियों पर दूसरे संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई कराधान अथवा तत्संबंधी ऐसी कोई अपेक्षा लागू नहीं होगी, जो उस कराधान से और उन संबंधित अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अपेक्षाकृत अधिक भारपूर्ण हो, जो उस दूसरे राज्य के राष्ट्रियों पर एक समान परिस्थितियों तथा एक समान शर्तों में लागू होती है अथवा हो सकती है।

2. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के दूसरे संविदाकारी राज्य में किसी स्थायी संस्थापन पर, उस दूसरे राज्य में ऐसा कराधान लागू नहीं किया जाएगा जो उस दूसरे राज्य के उद्यमों पर एक समान परिस्थितियों में तथा एक समान शर्तों के अधीन समरूप कार्यकलापों को करने के लिए लागू होने वाले कराधान से अपेक्षाकृत कम अनुकूल हो।

3. इस अनुच्छेद में, निहित किसी भी अर्थ का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि एक संविदाकारी राज्य की उन व्यक्तियों को, जो उस राज्य के निवासी नहीं हैं, कराधान के प्रयोजनार्थ किसी प्रकार की व्यक्तिगत

छूट, राहत, कटौतियाँ, तथा कटौतियाँ मंजूर करने के लिए, जो कि कानून द्वारा केवल ऐसे व्यक्तियों को उपलब्ध हैं, जो वहाँ के निवासी हैं, अपेक्षित करता है।

4. एक संविदाकारी राज्य के उद्यमों पर, जिनकी पूँजी पूर्णतः अथवा अंशतः दूसरे संविदाकारी राज्य के एक अथवा एक से अधिक निवासियों के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष स्वामित्व में अथवा नियंत्रण में है, प्रयोजित संबंधकारी राज्य में ऐसा कोई कराधान अथवा तत्संबंधी कोई भी अपेक्षा लागू नहीं की जाएगी, जो उस कराधान से अथवा तत्संबंधी किसी भी अपेक्षाओं में, भिन्न अथवा अपेक्षाकृत अधिक भारपूर्ण है, जो प्रयोजित राज्य के अन्य समरूप उद्यमों पर एक समान परिस्थितियों और एक समान शर्तों के अधीन लागू होती है अथवा लागू हो सकती है।

5. इस अनुच्छेद में "कराधान" शब्द का अर्थ उन करों से है जो इस करार के विषय हैं।

अनुच्छेद 27

पारस्परिक करार कार्यविधि

1. जहाँ एक संविदाकारी राज्य का कोई निवासी यह समझता है कि एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों की कार्यविधियों के कारण उस पर इस प्रकार कर लगाया जाता है अथवा लगाया जाएगा जो इस करार के उपबंधों के अनुकूल नहीं है, तो वह, उन राज्यों के राष्ट्रिय कानूनों द्वारा उपबंधित उपायों के होते हुए भी, उस संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को अपना मामला प्रस्तुत कर सकता है जिसका यह निवासी है। यह मामला उस कार्यविधि के नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से, तीन वर्ष के अन्दर प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिसके कारण किया गया कराधान इस करार के अनुकूल नहीं है।

2. यदि सक्षम प्राधिकारी को आपत्ति उचित लगे और यदि वह स्वयं किसी समुचित हल पर पहुँचने में असमर्थ हो तो वह ऐसे कराधान के निवारण की दृष्टि से, जो इस करार के अनुकूल नहीं हैं, दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी के साथ परस्पर सहमति द्वारा उस मामले को हल करने का प्रयास करेगा। किए गए किसी भी समझौते को कार्यान्वित किया जाएगा चाहे संविदाकारी राज्यों के राष्ट्रिय कानूनों में कोई भी समय-सीमा क्यों न हो।

3. यदि इस करार की व्याख्या करने में अथवा इसे लागू करने में कोई कठिनाई अथवा बाधा उत्पन्न हो तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी उन्हें पारस्परिक सहमति से हल करने का प्रयास करेंगे। वे उन मामलों में भी दोहरे कराधान के निरसन के लिए परस्पर विचार-विमर्श कर सकते हैं जिनकी इस करार में उपस्था नहीं की गयी है।

4. पूर्ववर्ती पैराग्राफों के अभिप्राय में कोई समझौता करने के प्रयोजनार्थ संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी एक दूसरे के साथ संश्लेषण-व्यवहार भी कर सकते हैं। जहाँ समझौता करने की दृष्टि से विचारों का मौखिक आदान-प्रदान उपयुक्त समझा जाता हो तो इस प्रकार का विचार-विमर्श एक अयोग के माध्यम से किया जा सकता है जिसमें संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

अनुच्छेद 28

सूचना का आदान-प्रदान

1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना (जिसमें दस्तावेज भी शामिल हैं) का आदान-प्रदान करेंगे जो उन करार के उपबंधों को अथवा संविदाकारी राज्यों के उन करों में संबंधित अन्तरिक कानूनों के उपबंधों का कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक है, जो इस करार के अन्तर्गत होते हैं। जहाँ तक कि उनके अधीन विद्यमान कराधान व्यवस्था कराधान के प्रतिकूल नहीं हो तब कि विशेष रूप से ऐसे करों को जाबजुबी अथवा अपबंधन रोका जा सके। किसी भी संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की गयी कोई भी सूचना उचित प्रकार प्राप्त होगी जिस प्रकार कि उस राज्य के आन्तरिक कानूनों के अन्तर्गत प्राप्त की गयी सूचना माना जाय।

है। लेकिन, यदि सूचना भेजने वाले राज्य में सूचना को मूलतः गुप्त समझा जाता है तो, उसे केवल ऐसे व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों (जिनमें न्यायालय और प्रशासनिक निकाय भी शामिल हैं) को प्रकट किया जाएगा जो उन करों का निर्धारण अथवा जगती वसूली करने, उनके प्रवर्तन अथवा अभियोजन के संबंध में अथवा उनसे संबंधित प्रतीतों का निर्धारण करने से सम्बन्ध हों, जो करों के विषय हैं। ऐसे व्यक्ति अथवा प्राधिकारी सूचना का उपयोग केवल ऐसे प्रयोजनों के लिए करेंगे परन्तु वे सूचना को सार्वजनिक न्यायालय की कार्यवाही अथवा न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकेंगे। सक्षम प्राधिकारी, विचार-विमर्श के माध्यम से उन मामलों से संबंधित सम्बन्धित भागों, पद्धतियों और तकनीकों को विकसित करेंगे, जिनके बारे में सूचना का ऐसा आदान-प्रदान किया जाएगा जिनमें, जहाँ कहीं उपयुक्त हों, कर प्रवर्तन के संबंध में सूचना का आदान-प्रदान भी शामिल है।

2. सूचना अथवा दस्तावेजों का आदान-प्रदान या तो नेरी आधार पर अथवा मामलों विशेष के सम्बन्ध में अनुरोध करने पर अथवा दोनों स्थितियों में किया जा सकेगा। संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी समय-समय पर, ऐसी सूचना अथवा दस्तावेजों की सूची से सहमत होंगे, जिन्हें नेरी आधार पर प्रस्तुत किया जाएगा।

3. किसी भी स्थिति में, पैराग्राफ 1 के उपबंधों का अर्थ किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित दायित्व डालना नहीं होगा :

- (क) उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य की विधियों अथवा प्रशासनिक प्रथा से हटकर प्रशासनिक उपाय करना,
- (ख) ऐसी सूचना अथवा दस्तावेजों की सत्यापन करना जो उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अन्तर्गत अथवा प्रशासन की संभाव्य स्थिति में प्राप्य नहीं हैं।
- (ग) ऐसी सूचना अथवा दस्तावेजों की सत्यापन करना जिसे कोई व्यापारिक, व्यावसायिक, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा रोजगार संबंधी गुप्त सेवा अथवा व्यापारिक प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हो अथवा सूचना जिसको प्रकट करना सरकार की नीति के प्रतिकूल है।

अनुच्छेद 29

वसूली में सहायता

1. संविदाकारी राज्य ऐसे करों की वसूली करने में एक दूसरे की सहायता करने और उसे समर्थन देने का जिम्मा लेने हैं जिससे यह करार संबंधित है और जहाँ वे कर अनुरोध करने वाले राज्य के कानूनों के अनुसार निश्चित रूप से संदेय होते हैं।

2. दोनों में से किसी भी संविदाकारी राज्य के कर संबंधी दावों की वसूली करने के लिए, जिन्हें अन्तिम रूप से निर्धारित किया गया है, प्राप्त अनुरोध के मामले में, दूसरे संविदाकारी राज्य द्वारा, जिसे अनुरोध किया जाता है, लागू करने के लिए स्वीकार किया जाएगा तथा उस राज्य में उसके करों को लागू करने तथा उनकी वसूली करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले कानूनों के अनुसार वसूली जाएगा।

3. भारतीय कर के मामले में जर्मन जनवादी गणराज्य के बिन मंत्रालय को, राजस्व विभाग, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा अनुरोध किया जाएगा तथा उसके साथ भारतीय कानूनों के अनुसार यथापेक्षित ऐसा प्रमाण-पत्र यह प्रमाणित करने के लिए संलग्न किया जाएगा कि संगत अतिरिक्त कानूनों के आधार पर उसके करों को अन्तिम रूप से निर्धारित किया गया है तथा वे करदाताओं की ओर बकाया हैं।

4. जर्मन जनवादी गणराज्य के कर के मामले में वहाँ के बिन मंत्रालय द्वारा भारत में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व विभाग को अनुरोध किया जाएगा तथा उसके साथ जर्मन जनवादी गणराज्य के कानूनों के अनुसार यथापेक्षित ऐसा प्रमाणित यह प्रमाणित करने के लिए भेजा

जाएगा कि संगत आन्तरिक कानूनों के आधार पर उसके करों को अन्तिम रूप से निर्धारित किया गया है तथा वे करदाताओं की ओर बकाया हैं।

5. जहाँ कर संबंधी कोई दावा उसके अन्तिम के अन्तिम होने अथवा किसी अन्य कार्यवाही के कारण अन्तिम रूप में देय नहीं होता हो तो उस मामले में एक संविदाकारी राज्य अपने राजस्व को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से, दूसरे संविदाकारी राज्य के इस संबंध में ऐसे आन्तरिक उपाय करने के लिए अनुरोध कर सकता है जो उस दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अन्तर्गत विधि संगत हैं।

6. किसी करदाता से संबंध करों की वसूली किए जाने में सहायता करने के लिए अनुरोध केवल तभी किया जाएगा यदि अनुरोध करने वाले संविदाकारी राज्य में करदाता ने करों की वसूली किए जाने के लिए अपनी पर्याप्त आग अथवा परिसंपत्तियाँ उपलब्ध नहीं हों।

7. वह संविदाकारी राज्य, जिसमें इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1, 2 तथा 5 के अनुसरण में कर की वसूली की जाती है, उसके तत्काल परवर्ती इस प्रकार वसूल की गयी रकम को उस संविदाकारी राज्य को भेजेगा जिसने इसके लिए अनुरोध किया था परन्तु वह ऐसे कर की वसूली करने में की गयी मद के दौरान किए गए व्यय, यदि कोई हो, की लागत के लिए हक्काज होगा परन्तु किसी भी हालत में ऐसी लागत की मात्रा वसूल की गयी रकम के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो।

अनुच्छेद 30

राजनयिक और कौसली कार्यकाल

इस करार की किसी भी बात से राजनयिक अथवा कौसली अधिकारियों को अन्तरराष्ट्रीय कानून के सामान्य नियमों के अन्तर्गत अथवा विशेष करारों के उपबंधों के अन्तर्गत प्राप्त वित्तीय विवेकाधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुच्छेद 31

प्रवर्तन

1. इस करार का अनुसमर्थन और अनुमोदन दोनों संविदाकारी राज्यों में प्रवर्तमान कानूनों के अनुसार किया जाएगा।

2. यह करार, प्रवर्तमान कानूनों के अनुसार करार के अनुमोदन अथवा अनुसमर्थन को अधिसूचित करने वाली दिवसियों के आदान-प्रदान पर प्रवृत्त होगा।

3. इस करार के उपबन्ध निम्नलिखित पर लागू होंगे :

(क) भारत गणराज्य में, इस करार के अन्तर्गत आने वाले कर, जो अप्रैल, 1985 के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद आरम्भ होने वाले किसी कर-निर्धारण वर्ष के लिए लगाए जाते हैं ;

(ख) जर्मन जनवादी गणराज्य में, इस करार के अन्तर्गत आने वाले कर, जो जनवरी, 1985 के द्वितीय दिन को अथवा उसके बाद आरम्भ होने वाले किसी कर-निर्धारण वर्ष के लिए लगाए जाते हैं।

अनुच्छेद 32

बैकान अन्वेष

1. यह करार अन्तिम अन्वेष के लिए सम्पन्न किया जाता है, परन्तु दोनों में से कोई भी संविदाकारी राज्य करार के प्रवृत्त होने के दिन से पाँच वर्ष के पश्चात निश्चित नोटिस देकर इस करार-अनुको समाप्त कर सकता है, तथापि, नोटिस इस प्रकार दिया जाए कि सि कैलेण्डर वर्ष में नोटिस दिया जाता है उसके समाप्त होने में कम से कम छः महीने शेष हों।

2. ऐसी स्थिति में यह सरकार निम्नलिखित के बारे में निम्नप्रभावी हो जाएगी :

(क) भारत गणराज्य में, जिस कैलेंडर वर्ष में नाट्य दिनांक होता है उस वर्ष के परवर्ती जनवरी के प्रथम दिन को अथवा उसके पश्चात् आरम्भ होने वाले पूर्ववर्ती किसी वर्ष में उद्भूत आय के संबंध में,

(ख) जर्मन जनवादी गणराज्य में, जिस कैलेंडर वर्ष में कटार के पर्यवसान का नाट्य दिनांक होता है उस वर्ष के परवर्ती जनवरी के प्रथम दिन को अथवा उसके पश्चात् आरम्भ होने वाले किसी आय वर्ष में उद्भूत होने वाली आय के संबंध में।

जिसके माध्यम से, इसके लिए विधिवत प्राधिकृत अधिकृत अधिकारियों ने वर्तमान कटार पर हस्ताक्षर किए हैं।

नई दिल्ली में वर्ष एक हजार नौ सौ नवमों के जुलाई मास के छब्बीसवें दिन को, हिन्दी, जर्मन तथा अंग्रेजी भाषाओं में बराबर प्रतियों में सम्पन्न किया गया, इसके सर्वाधिकार समान रूप से प्रामाणिक हैं। इन दोनों पाठों में से किसी के बीच कोई भिन्नता के मामले में अंग्रेजी पाठ प्रभावी होगा।

भारत गणराज्य की सरकार की ओर से

जर्मन जनवादी गणराज्य की सरकार की ओर से

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

(पी. के. अग्रवाल)

(डॉ. प्रदीप)

[प्रसिद्धि सं. 8588/फा. सं. 501/10/78-एक.सी. पी.]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(Foreign Tax Division)

New Delhi, the 2nd March, 1990

NOTIFICATIONS

INCOME-TAX

G.S.R. 107(E).—Whereas the annexed Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the German Democratic Republic for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and on capital has come into force on the 24th November, 1989, on the notification by both the Contracting States to each other of the approval of the Agreement under their laws in accordance with Article 31 of the said Agreement;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 44-A of the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957), and section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby directs that all the provisions of the said Agreement shall be given effect to in the Union of India.

ANNEXURE

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA AND THE GOVERNMENT OF THE GERMAN DEMOCRATIC REPUBLIC FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL

AGREEMENT

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA AND

THE GOVERNMENT OF THE GERMAN DEMOCRATIC REPUBLIC

FOR

THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL

The Government of the Republic of India and the Government of the German Democratic Republic; Desiring

to promote economic co-operation between the two States through an Agreement for the Avoidance of Double Taxation with respect to Taxes on Income and on Capital;

Have agreed as follows :—

Article 1

PERSONAL SCOPE

This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2

TAXES COVERED

1. The taxes to which this Agreement shall apply are :—

(a) in the Republic of India :

(i) the income-tax including any surcharge thereon imposed under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961); and

(ii) the wealth-tax imposed under the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957); (hereinafter referred to as "Indian tax")

(b) in the German Democratic Republic :

(i) Einkommensteuer (Income-tax);

(ii) Koerperschaftsteuer (Corporate income tax);

(iii) Gewinnabfuhrungen der Staatlichen Betriebe (Revenue transfer by public enterprises);

(iv) Lohnsteuern (Tax on wages);

(v) Steuer auf Lizenzgebuehren (Tax on Royalties);

(vi) Gewerbesteuer (Trade tax); and

(vii) Vermoegensteuer (Property tax) (hereinafter referred to as "German Democratic Republic tax").

2. The Agreement shall also apply to any identical or substantially similar taxes which are imposed by either Contracting State after the date of signature of the present Agreement in addition to, or in place of, the taxes referred to in paragraph 1. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any substantial changes which are made in their respective taxation laws.

Article 3

GENERAL DEFINITIONS

1. In this Agreement, unless the context otherwise requires :—

(a) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean Republic of India or the German Democratic Republic as the context requires,

(b) the term "tax" means Indian tax or German Democratic Republic tax as the context requires, but shall not include any amount which is payable in respect of any default or omission in relation to the taxes to which this Agreement applies or which represents a penalty imposed relating to those taxes;

(c) the term "person" includes an individual, a company and any other entity which is treated as a taxable unit under the taxation laws in force in the respective Contracting States;

(d) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a company or body corporate under the taxation laws in force in the respective Contracting States;

(e) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;

(f) the term "competent authority" means in the case of India, the Central Government in the Ministry of Finance (Department of Revenue) or their authorised representative; and in the case of the German Democratic Republic, the Ministry of Finance;

(g) the term "national" means :—

(i) any individual, possessing the nationality of a Contracting State under the laws in force in that State; and

(ii) any legal person, partnership or organisation deriving its status from the laws in force in the Contracting State;

(h) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State.

2. As regards the application of the Agreement by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has for the purposes of the law of that State concerning the taxes to which the Agreement applies.

Article 4

RESIDENT

1. For the purposes of this Agreement, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1, an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows :—

(a) he shall be deemed to be a resident of the State in which he has a permanent home available to him, if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);

(b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident of the State in which he has an habitual abode;

(c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the State of which he is a national;

(d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1, a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the State in which its place of effective management is situated.

Article 5

PERMANENT ESTABLISHMENT

1. For the purposes of this Agreement, the term "permanent establishment" means a fixed place of business

through which the business of the enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term "permanent establishment" includes especially :—

(a) a place of management;

(b) a branch;

(c) an office;

(d) a factory;

(e) a workshop or a warehouse;

(f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources;

(g) a farm or plantation;

(h) a premises used as a sales outlet or for receiving or soliciting orders;

(i) an installation or structure used for the exploration or development of natural resources;

(j) a building site or construction, installation or assembly project or supervisory activities in connection therewith, where such site, project or activities (together with other such sites, projects or activities, if any) continue for a period of more than six months.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to include :

(a) a temporary building site or construction or installation project executed by the Government of a Contracting State in the other State;

(b) the use of facilities solely for the purpose of storage or display of goods or merchandise belonging to the enterprise;

(c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage or display;

(d) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;

(e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise, or of collecting information, for the enterprise;

(f) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, for the supply of information, for scientific research, or for similar activities which have a preparatory or auxiliary character, for the enterprise.

However, the provisions of sub-paragraphs (b) to (f) shall not be applicable where the enterprise maintains any other fixed place of business in the other Contracting State for any purposes other than the purposes specified in the said sub-paragraphs.

4. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2 where a person—other than an agent of an independent status to whom paragraph 5 applies—is acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in the first-mentioned State, if

(a) he has and habitually exercises in that State an authority to conclude contracts on behalf of the enterprise, unless his activities are limited to the purchase of goods or merchandise for the enterprise;

(b) he has no such authority, but habitually maintains in the first-mentioned State a stock of goods or merchandise from which he regularly delivers goods or merchandise on behalf of the enterprise; or

(c) he habitually secures orders in the first-mentioned State, wholly or almost wholly for the enterprise itself or for the enterprise and other enterprises controlling, controlled by, or subject to the same common control as, that enterprise.

5. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status provided that such persons are acting in the ordinary course of their business. However, when the activities of such an agent are devoted wholly or almost wholly on behalf of that enterprise itself or on behalf of that enterprise and other enterprises controlling, controlled by, or subject to the same common control, as that enterprise, he will not be considered an agent of an independent status within the meaning of this paragraph.

6. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other Contracting State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

Article 6

INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of the law of the Contracting State respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources.

Ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall also apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

Article 7

BUSINESS PROFITS

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as are attributable to (a) that permanent establishment; (b) sales in that other State of goods or merchandise of the same or similar kind as those sold through that permanent establishment; or (c) other business activities carried on in that other State of the same or similar kind as those effected through that permanent establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment. In any case where the correct amount of profits attributable to a permanent establishment is incapable of determination or the determination thereof presents exceptional difficulties, the profits attributable to the permanent establishment may be estimated on a reasonable basis.

3. In the determination of the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the business of the permanent establishment including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere, in accordance with the provisions of and subject to the limitations of the taxation laws of that State. However, no such deduction shall be allowed in respect of amounts, if any, paid (otherwise than towards reimbursement of actual expenses) by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents, know-how or other rights, or by way of commission or other charges for specific services performed or for management, or, except in the case of a banking enterprise, by way of interest on moneys lent to the permanent establishment. Likewise, no account shall be taken, in the determination of the profits of a permanent establishment, for amounts charged (otherwise than towards reimbursement of actual expenses) by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents, know-how or other rights, or by way of commission or other charges for specific services performed or for management, or, except in the case of a banking enterprise, by way of interest on moneys lent to the head office of the enterprise or any of its other offices.

4. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

5. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

6. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Agreement, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Article 8

AIR TRANSPORT

1. Profits derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of aircraft in international traffic shall be taxable only in that State.

2. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool, joint business or an international operating agency.

3. For the purposes of this Article, interest on funds connected with the operation of aircraft in international traffic shall be regarded as profits derived from the operation of such aircraft, and the provisions of Article 12 shall not apply in relation to such interest.

4. The term "operation of aircraft" shall mean business of transportation by air of passengers, mail, livestock or goods carried on by the owners or lessors or charterers of aircraft, including the sale of tickets for such transportation on behalf of other enterprises, the incidental lease of aircraft

and any other activity directly connected with such transportation.

Article 9

SHIPPING

1. Income derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of ships in international traffic may be taxed in the other Contracting State.

2. No income tax and/or turnover tax shall be levied or collected by the Government of the German Democratic Republic on the freight earning and/or profits on national cargo carried by the Indian vessels including those under time-charter between ports of the two States, and similarly no income tax and/or turnover tax shall be levied or collected by the Government of the Republic of India on the freight earnings and/or profits on national cargo carried by the vessels of the German Democratic Republic including those under time-charter between ports of the two States.

3. Income derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of ships in international traffic for the transport of cargo other than that belonging to either Contracting state may be taxed also in that other Contracting State; but such tax shall be restricted to 50 per cent of the tax otherwise leviable in the source country.

4. The provisions of this Article shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency engaged in the operation of ships.

5. For the purposes of this Article :

- (a) interest on funds connected with the operation of ships in international traffic shall be regarded as income from the operation of such ships and the provisions of Article 12 shall not apply in relation to such interest; and
- (b) income from the operation of ships includes income derived from the use, maintenance or rental of containers (including trailers and related equipment for the transport of containers) in connection with the transport of goods or merchandise in international traffic.

Article 10

ASSOCIATED ENTERPRISES

Where :

- (a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or
- (b) the same persons participate directly or indirectly in the management control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State.

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises then any profits which would but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

Article 11

DIVIDENDS

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the dividends, the tax so charged shall not exceed :

- (a) 15 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company which owns at least 25 per cent of the shares of the company paying the dividends;
- (b) 25 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7, or Article 15, as the case may be, shall apply.

5. Where a company which is a resident of a Contracting State denies profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company except in so far as such dividends are paid to a resident of that other State or so far as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits of income arising in such other State.

Article 12

INTEREST

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the interest.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2,

- (a) interest arising in a Contracting State shall be exempt from tax in that State provided it is derived and beneficially owned by :
 - (i) the Government, a political sub-division or a local authority of the other Contracting State; or
 - (ii) the Central Bank of the other Contracting State;

- (b) interest arising in a Contracting State shall be exempt from tax in that Contracting State to the extent approved by the Government of that State if it is derived and beneficially owned by any person other than a person referred to in sub-paragraph (a) who is resident of the other Contracting State provided that the transaction giving rise to the debt-

claim has been approved in this regard by the Government of the first mentioned Contracting State.

4. The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein and the debt-claim in respect of which the interest paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7 or Article 15, as the case may be, shall apply.

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that Contracting State itself, a political sub-division, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

Article 13

ROYALTIES AND FEES FOR TECHNICAL SERVICES

1. Royalties and fees for technical services arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such royalties and fees for technical services may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties, or fees for technical services, the tax so charged shall not exceed 22.5 (twenty two and a half) per cent of the gross amount of the royalties or fees for technical services.

3. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work, including cinematograph films or tapes used for radio or television broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

4. The term "fees for technical services" as used in this Article means payments of any amount to any person other than payments to an employee of a person making payments, in consideration for the services of a managerial, technical or consultancy nature, including the provision of services of technical or other personnel.

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties or fees for technical services, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties or fees for technical services arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right, property or contract in respect of which the royalties or fees for technical services are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7 or Article 15, as the case may be, shall apply.

6. Royalties and fees for technical services shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political sub-division, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties or fees for technical services, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties or fees for technical services was incurred, and such royalties or fees for technical services are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties or fees for technical services shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7. Where, by reason of special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of royalties or fees for technical services paid exceeds the amount which would have been paid in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

Article 14

CAPITAL GAINS

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property, referred to in Article 6, and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or together with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State.

3. Gains from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

4. Gains from the alienation of shares of the capital stock of a company the property of which consists directly or indirectly principally of immovable property situated in a Contracting State may be taxed in that State.

5. Gains from the alienation of shares other than those mentioned in paragraph 4 in a company which is a resident of a Contracting State may be taxed in that State.

6. Gains from the alienation of any property other than that mentioned in paragraphs 1, 2, 3, 4 and 5 shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

Article 15

INDEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Income derived by an individual who is a resident of a Contracting State from the performance of professional

services or other independent activities of a similar character shall be taxable only in that State except in the following circumstances when such income may also be taxed in the other Contracting State :

- (a) If he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities; in that case, only so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in that other State ; or
- (b) if his stay in the other Contracting State is for a period or periods amounting to or exceeding in the aggregate 90 days in the relevant "previous year" or "year of income", as the case may be; in that case, only so much of the income as is derived from his activities performed in that other State may be taxed in that other State.

2. The term "professional services" includes independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, surgeons, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

Article 16

DEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Subject to the provisions of Articles 17, 18, 19, 20, 21 and 22, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if :

- (a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in the relevant "fiscal year", as the case may be; and
- (b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State ; and
- (c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State may be taxed in that State.

4. Experts of either Contracting State delegated to the other Contracting State under Agreements for Scientific Exchanges and Cooperation between India and the German Democratic Republic in force from time to time, shall be exempted by the other State from payment of income-tax on the salaries and allowance paid to them by their respective States.

Article 17

DIRECTORS' FEES AND REMUNERATION OF TOP LEVEL MANAGERIAL OFFICIALS

1. Directors' fees and similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the Board of Directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. Salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in his capacity as an official in a top-level managerial position of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

Article 18

INCOME EARNED BY ENTERTAINERS

Notwithstanding the provisions of Articles 15 and 16, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer such as a theatre, motion picture, radio or television artiste or a musician from his personal activities as such exercised in the other Contracting State may be taxed in that other State :

Provided that income derived by individuals or groups of persons from activities exercised in the framework of cultural exchanges agreed between the Contracting States on a bilateral or multilateral basis may be taxed only in the State of which they are residents.

Article 19

REMUNERATION AND PENSIONS IN RESPECT OF GOVERNMENT SERVICE

1. (a) Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political sub-division or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or sub-division or authority shall be taxable only in that State.

(b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that other State and the individual is a resident of that State who :

- (i) is a national of that State ; or
- (ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.

2. (a) Any pension paid by, or out of funds created by a Contracting State or a political sub-division or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or sub-division or authority shall be taxable only in that State.

(b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of that other State.

3. The provisions of Articles 16, 17 and 18 shall apply to remuneration and pensions in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political sub-division or local authority thereof.

Article 20

NON-GOVERNMENT PENSIONS AND ANNUITIES

1. Any pension other than a pension referred to in Article 19, or any annuity derived by a resident of a Contracting State from sources within the other Contracting State may be taxed only in the first-mentioned Contracting State.

2. The term "pension" means a periodic payment made in consideration of past services or by way of compensation for injuries received in the course of performance of services.

3. The term "annuity" means a stated sum payable periodically at stated times during life or during a specified or ascertainable period of time, under an obligation to make the payments in return for adequate and full consideration in money or money's worth.

Article 21

PAYMENTS RECEIVED BY STUDENTS AND APPRENTICES

1. A student or business apprentice who is or was a resident of one of the Contracting States immediately before visiting the other Contracting State and who is present in that other

State solely for the purpose of his education or training, shall be exempt from tax in that other State on :

- (a) payments made to him by persons residing outside that other State for the purposes of his maintenance, education or training ; and
- (b) remuneration from employment in that other State in an amount not exceeding Rs. 15,000 or its equivalent in "Mark of the GDR" during any "previous year" or the "year of income", as the case may be, provided that such employment is directly related to his studies or is undertaken for the purpose of his maintenance.

2. The benefits of this Article shall extend only for such period of time as may be reasonable or customarily required to complete the education or training undertaken, but in no event shall any individual have the benefits of this Article, for more than six consecutive years from the date of his first arrival in that other Contracting State.

Article 22

PAYMENTS RECEIVED BY PROFESSORS, TEACHERS AND RESEARCH SCHOLARS

1. A professor or teacher who is or was a resident of one of the Contracting States immediately before visiting the other Contracting State for the purpose of teaching or engaging in research, or both, at a university, college, school or other approved institution in that other Contracting State shall be exempt from tax in that other State on any remuneration for such teaching or research for a period not exceeding two years from the date of his arrival in that other State.

2. This Article shall not apply to income from research if such research is undertaken primarily for the private benefit of a specific person or persons.

3. For the purposes of this Article and Article 21, an individual shall be deemed to be a resident of a Contracting State if he is resident in that Contracting State in the "previous year" or the "year of income", as the case may be, in which he visits the other Contracting State or in the immediately preceding "previous year" or the "year of income".

4. For the purposes of paragraph 1, "approved institution" means an institution which has been approved in this regard by the competent authority of the concerned Contracting State.

Article 23

OTHER INCOME

1. Subject to the provisions of paragraph 2, items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, which are not expressly dealt with in the foregoing Articles of this Agreement, shall be taxable only in that Contracting State.

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7 or Article 15, as the case may be, shall apply.

3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, items of income of a resident of a Contracting State not dealt with in the foregoing Articles of this Agreement and arising in the other Contracting State may be taxed in that other State.

615 GT/90—3

Article 24

CAPITAL

1. Capital represented by immovable property referred to in Article 6, owned by a resident of a Contracting State and situated in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

2. Capital represented by movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or by movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, may be taxed in that other State.

3. Capital represented by ships or aircraft, operated in international traffic and by movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in the Contracting State of which the enterprise owning such property is a resident.

4. All other elements of capital of a resident of a Contracting State may be taxed in both Contracting States.

Article 25

ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

1. The laws in force in either of the Contracting States shall continue to govern the taxation of income and capital in the respective Contracting State except where express provision to the contrary is made in this Agreement.

2. Where a resident of a Contracting State derives income or owns capital which, in accordance with the provisions of this Agreement may be taxed in the other Contracting State, the first-mentioned State shall, subject to the provisions of paragraph 3, exempt such income or capital from tax.

3. Where in accordance with any provisions of the Agreement income derived or capital owned by a resident of a Contracting State is exempt from tax in that State, such State may nevertheless, in calculating the amount of tax on the remaining income or capital of such resident, take into account the exempted income or capital.

Article 26

NON-DISCRIMINATION

1. The nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation, and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances and under the same conditions are or may be subjected.

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities in the same circumstances and under the same conditions.

3. Nothing contained in this Article shall be construed as obliging a Contracting State to grant to persons not resident in that State any personal allowance, reliefs, reductions and deductions for taxation purposes which are by law available only to persons who are so resident.

4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of that first-mentioned State are or may be subjected in the same circumstances and under the same conditions.

5 In this Article, the term "taxation" means taxes which are the subject of this Agreement.

Article 27

MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

1. Where a resident of a Contracting State considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with this Agreement, he may, notwithstanding the remedies provided by the national laws of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident. The case must be presented within three years of receipt of notice of the action which gives rise to taxation not in accordance with the Agreement.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at an appropriate solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to avoidance of taxation not in accordance with the Agreement. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the national laws of the Contracting States.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Agreement. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Agreement.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. When it seems advisable in order to reach agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place through a Commission consisting of representatives of the competent authorities of the Contracting States.

Article 28

EXCHANGE OF INFORMATION

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information (including documents) as is necessary for carrying out the provisions of the Agreement or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by the Agreement, in so far as the taxation thereunder is not contrary to the Agreement, in particular for the prevention of fraud or evasion of such taxes. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State. However, if the information is originally regarded as secret in the transmitting State, it shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes which are the subject of the Agreement. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes but may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. The competent authorities shall, through consultation, develop appropriate conditions, methods and techniques concerning the matters in respect of which such exchange of information shall be made, including, where appropriate, exchange of information regarding tax avoidance.

2. The exchange of information or documents shall be either on a routine basis or on request with reference to particular cases or both. The competent authorities of the Contracting States shall agree from time to time on the list of the information or documents which shall be furnished on a routine basis.

3. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation :

- (a) to carry out administrative measures at variance with the laws or administrative practice of that or of the other Contracting State ;

- (b) to supply information or documents which are not obtainable under the laws or in the normal course of the administrative of that or of the other Contracting State ;

- (c) to supply information or documents which would disclose any trade, business, industrial commercial or professional secret or trade process or information the disclosure of which would be contrary to public policy.

Article 29

ASSISTANCE IN COLLECTION

The Contracting States undertake to lend assistance and support to each other, in the collection of the taxes to which this Agreement relates. In the cases where the taxes are definitely due according to the laws of the State making the request,

2. In the case of a request for enforcement of collection, tax claims of either of the Contracting States which have been finally determined will be accepted for enforcement by the other Contracting State to which the request is made and collected in that State in accordance with the laws applicable to the enforcement and collection of its taxes.

3. In the case of Indian tax, the request will be sent by the Central Board of Direct Taxes, Department of Revenue to the Ministry of Finance of the German Democratic Republic, and will be accompanied by such certificate as is required by the laws of India to establish that the taxes have been finally determined on the basis of the relevant domestic laws, and are due from the taxpayer.

4. In the case of the German Democratic Republic tax, the request will be sent by the Ministry of Finance to the Central Board of Direct Taxes, Department of Revenue, in India and will be accompanied by such certificate as is required by the laws of the German Democratic Republic to establish that the taxes have been finally determined on the basis of the relevant domestic laws and are due from the taxpayer.

5. Where the tax claim has not become final by reason of its being subject to appeal or any other proceeding, a Contracting State may, in order to protect its revenues, request the other Contracting State to take such interim measures in this behalf as are lawful under the laws of that other Contracting State.

6. A request for assistance in collection of taxes due from a taxpayer shall be made only if adequate income or assets of that taxpayer are not available for recovering the taxes from him in the Contracting State making the request.

7. The Contracting State in which tax is covered in pursuance of paragraphs 1, 2 and 5 of this Article shall immediately thereafter remit the amount so recovered to the Contracting State which made the request but it shall be entitled to reimbursement of costs, if any, incurred in the course of rendering assistance in the recovery of such tax but in no event, such cost shall exceed 10 per cent of the amount so recovered.

Article 30

DIPLOMATIC AND CONSULAR ACTIVITIES

Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges of diplomatic or consular officials under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Article 31

ENTRY INTO FORCE

1. This Agreement shall be ratified or approved in accordance with the laws in force in the two Contracting States.

2. This Agreement shall enter into force upon the exchange of notes notifying the approval or ratification of the Agreement in accordance with the laws in force.

3. The provisions of the Agreement shall apply :

- (a) in the Republic of India, to taxes covered by this Agreement which are levied for any year of assessment, beginning on or after the first day of April, 1985 ;
- (b) in the German Democratic Republic, to taxes covered by this Agreement which are levied for any year of assessment, beginning on or after the first day of January, 1985.

Article 32

PERIOD OF VALIDITY

1. This Agreement is concluded for unlimited duration but either Contracting State may terminate the Agreement by giving written notice after five years from the days of its entry into force, so however, that at least six months remain before the end of the calendar year in which the notice is given.

2. In such event, the Agreement shall cease to have effect :

- (a) in the Republic of India, in respect of income arising in any previous year beginning on or after the 1st day of April next following the calendar year in which the notice is given ;
- (b) in the German Democratic Republic, in respect of income arising in any year of income beginning on or after the 1st day of January next following the calendar year in which the notice of termination is given.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed the present Agreement.

Done in duplicate at New Delhi this twenty sixth day of July one thousand nine hundred and eighty nine in the Hindi, German and English languages; all the texts being equally authentic. In case of divergence between any of the two texts, the English text shall be the operative one.

For the Government of the
Republic of India

Sd/-

(P. K. APPACHOO)

For the Government of the
German Democratic Republic

Sd/-

(W. GRABOWSKI)

[Notification No. 8588/F. No. 5010/10/78-FTD]

म. का. नि. 108 (अ) - केन्द्रीय सरकार, धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की धारा 44क के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने द्वारा, जर्मन जनवादी गणराज्य को उस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, अतिरिक्त देश घोषित करती है।

[अधिसूचना सं. 8589/फा. सं. 501/10/78-एफ टी डी]
पी. के. अपाचू, संयुक्त सचिव

G.S.R. 108(E).—In exercise of the powers conferred by the Explanation to section 44-A of the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957), the Central Government hereby declares the German Democratic Republic to be a reciprocating country for the purposes of that Act.

[Notification No. 8589/F. No. 501/10/78-FID]
P. K. APPACHOO, Jt. Secy.

